Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to fill up vacant posts in government offices and departments and also to regularise the services of contractual/temporary employees working in government sector.

श्री हरीश मीना (दौसा): मैं सरकार का ध्यान एक जरुरी मसले की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ । सरकारी क्षेत्र की नौकरियों के निजीकरण, अस्थाईकरण आदि से देश के युवाओं के बीच गंभीर निराशा है । सरकारी नौकरियों में लगातार कटौती हो रही है और पुराने खाली पड़े पदों को भरा नहीं जा रहा है। निजी क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है । यह सच है कि निजी क्षेत्र के आने से कर्मचारियों में प्रतियोगिता की भावना का विकास हुआ है और उनकी कार्य क्षमता बढ़ी है लेकिन निजी क्षेत्र के अनियंत्रित विस्तार से भारतीय संविधान सम्मत सामाजिक न्याय के विचार को बहुत नुकसान हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और आर्थिक रुप से कमजोर तबकों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है । इससे देश के वंचित तबकों में निराशा और प्रतिरोध का भाव पनप रहा है । पिछलों दिनों सरकार ने अत्यंत उच्च पदों यानि संयुक्त सचिव जैसे बेहद अहम पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन निकाला है । सबके दिमाग में यही सवाल है कि सिविल सेवा से निकले एक से बढ़कर एक अधिकारियों के होते इस सीधी भर्ती की आवश्यकता क्यों पड़ी ? इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निजीकरण बहुत तेजी से फैल रहा है । यह निजीकरण सिर्फ पूंजीपतियों के लिए लाभदायक हो सकता है क्योंकि इसकी मदद से उन्हें सस्ता श्रम मिल जाता है और उनका मुनाफा बेहिसाब बढ़ता जाता है । एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए इस तरह नौकरियों का अंधाधुंध निजीकरण उचित नहीं जान पड़ता है।

मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस ओर ध्यान दे और सामाजिक न्याय व संविधान की रक्षा हेतु समुचित उपाय कर खाली पदों पर शीघ्र नियुक्तियां की जायें तथा सरकारी महकमों में संविदा या अस्थाई तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन व अन्य सुविधायें मुहैया करायी जायें।